



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1994/चैत्र 10, 1916  
No. 160] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1994/CHAITRA 10, 1916

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

का. आ. 278 (अ)/18कक/आईडीआरए/94 - भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या - 320 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./79, तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स अपोली जिप्सम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (क) के अर्ध 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, वन्द और रंग उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल को, जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1994 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए इसे जारी रखने के लिए समय, समय पर निर्देश जारी किये थे। (देखिए भारत सचिव के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग के आदेश) :

सं. का. आ. 246 (अ)/18कक/आईडीआरए/82 तारीख 25 मई, 1982  
सं. का. आ. 832 (अ)/18कक/आईडीआरए/82 तारीख 24 नवम्बर, 1982  
सं. का. आ. 385 (अ)/18कक/आईडीआरए/83 तारीख 31 मार्च, 1983  
सं. का. आ. 872 (अ)/18कक/आईडीआरए/82, तारीख 30 नवम्बर, 1983  
सं. का. आ. 472 (अ)/18कक/आईडीआरए/84 तारीख 28 जून, 1984  
सं. का. आ. 975 (अ)/18कक/आईडीआरए/84 तारीख 29 दिसम्बर, 1984  
सं. का. आ. 275 (अ)/18कक/आईडीआरए/85 तारीख 29 मार्च, 1985  
सं. का. आ. 146 (अ)/18कक/आईडीआरए/86 तारीख 31 मार्च, 1986  
सं. का. आ. 266 (अ)/18कक/आईडीआरए/87 तारीख 30 मार्च, 1987  
सं. का. आ. 326 (अ)/18कक/आईडीआरए/88 तारीख 30 मार्च, 1988  
सं. का. आ. 247 (अ)/18कक/आईडीआरए/89, तारीख 31 मार्च, 1989  
सं. का. आ. 217 (अ)/18कक/आईडीआरए/90 तारीख 30 मार्च, 1990  
सं. का. आ. 214 (अ)/18कक/आईडीआरए/91, तारीख 26 मार्च, 1991  
सं. का. आ. 250 (अ)/18कक/आईडीआरए/92, तारीख 30 मार्च, 1992 और  
सं. का. आ. 219 (अ)/18कक/आईडीआरए/93, तारीख 31 मार्च, 1993

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1995 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे।

भारत केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक

के साथ पठित धारा 18A के की उपधारा (2) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमें यह सारीष भी सम्मिलित है और प्रवर्ति के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2/23/80 - सी यूएस/आई. धार. एस]  
सखण्ड प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 31st March, 1994

#### ORDER

S. O. 278(E)|18AA|IDRA|94.—Whereas by order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of said Industrial Undertaking.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1994 (Vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th 1982,

S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982.

S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st March, 1983,

S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983

S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,

S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985,

S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,

S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,

S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,

S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,

S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990,

S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,

S.O. 250(E)|18AA|IDRA|92, dated the 30th March, 1992 and

S.O. 219(E)|18AA|IDRA|93, dated the 31st March, 1993.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1995.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 18AA read with the proviso to Sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1995.

[F. No. 2(23)|80-CUS|IRS]

A. P. SINGH, Jt. Secy.